

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग

देहरादून दिनांक 04 मार्च 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में केन्द्रपोषित योजनाओं पर देय सेन्टेज की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उत्तराखण्ड पेयजल ससाधन विकास एवं निर्माण निगम को केन्द्रपोषित योजनाओं के निर्माण पर प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज चार्ज) भुगतान हेतु आपके पत्र संख्या 1781/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/79 दिनांक 05.08.10 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या 1185/उन्तीस(2)/10-2(60पे0)/2004 दिनांक 24 सितम्बर 2010 एवं शासनादेश संख्या 1520/उन्तीस(2)/10-2(60पे0)/2004 दिनांक 03 नवम्बर 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष देय सेन्टेज की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 900.00 लाख (रु० नौ करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष की 31.12.10 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2011 तक उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा एवं जो धनराशि दिनांक 31.03.2011 तक अप्रयुक्त रहती है उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5- उपरोक्त धनराशि का व्यय केन्द्रपोषित योजनाओं के निर्माण पर अनुमन्य की गई दर के सापेक्ष सम्बन्धित योजनाओं में योजनावार स्वीकृत अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के विरुद्ध शेष देय सेन्टेज की पूर्ति हेतु किया जायेगा।

6- सम्बन्धित केन्द्रपोषित योजनाओं पर भारत सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा कुल देय सेन्टेज की सीमा किसी भी दशा में अनुमन्य सीमा से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। इससे अधिक सेन्टेज पर व्यय होने की दशा में विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।



7- सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण हेतु समय-समय पर प्राप्त धनराशि जो बैंक में जमा रखी गई हो, में प्राप्त ब्याज की राशि का प्रमाणित विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा तथा ब्याज की राशि अध्याविधक पूर्ण शासन में जमा कर दी जायेगी।

8- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-00-07- केन्द्रपोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०-856/XXVII(2)/2011 दिनांक 07 मार्च 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

पृ० सं० 329(1)/उत्तीस(2)11-2(60पे०)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा० पेयजल मंजी जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2-स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

3-निजी सचिव-सचिव पेयजल को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

4-महालेखाकार, उत्तराखण्ड।

5- आयुक्त, गढ़वाल /कुमायूँ मण्डल।

6-वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून

7-निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई०सी० रोड, देहरादून।

✓ 8-निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

9-वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।

10-गार्ड फाईल।



आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)

संयुक्त सचिव